प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 47 अंक – 11 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 07 – 14 मार्च 2022 मूल्य पांच रूपए

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कर्ज और केंद्रीय सहायता पर मांगा श्वेत पत्र

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ऋणों को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कर्जो और केंद्र से मिली वित्तीय सहायता को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किये जाने की मांग की है। विपक्ष की इस मांग के परिदृश्य में सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। जयराम ठाकुर ने जब अपना पहला बजट भाषण 2018 में सदन में पढ़ा था तब यह जानकारी दी गई थी कि उन्हें 46385 करोड का कर्ज़ विरासत में मिला है। आज इस कार्यकाल का अंतिम बजट रखते हुये यह कर्ज करीब 70,000 करोड़ हो चुका है। इसी के साथ इस दौरान प्रधानमंत्री, गृहमत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो केंद्रीय सहायता के आंकड़े समय-समय पर प्रदेश की जनता को परोसे हैं उनके मुताबिक केंद्र प्रदेश को एक लाख करोड़ से अधिक की सहायता दे चुका है। मंडी की एक जनसभा में तो प्रधानमंत्री ने स्व. वीरभद्र सिंह से इसका हिसाब तक मांग लिया था। अमित शाह ने चंबा-कांगड़ा में इसे दोहराया है। उस समय छपी खबरें इसका प्रमाण है। जेपी नड्डा ने तो अभी पिछले दिनों ही 72,000 करोड़ की सहायता के आंकड़े को दोहराया है। इसी बीच जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने यह जानकारी भी सामने रखी है कि सरकार को 12000 करोड के ऐसे धन का भी पता चला है जो कि खर्च ही नहीं किया गया है। इसकी पूरी जानकारी अधिकारियों से ली गयी है। केंद्र की सहायता के जो आंकड़े इन तीन शीर्ष नेताओं ने प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं उन पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं बनता है।

पिछले दिनों आयी कैग रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया है कि सरकार ने 96 योजनाओं पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है। कैग के इस खुलासे का सरकार ने कोई खंडन नहीं किया है। जयराम सरकार पर विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि प्रदेश को कर्ज में डुबोया जा रहा है। यहां पर यह समझना आवश्यक है की एफ आर बी एम के मुताबिक सरकार अपने प्रतिबद्ध खर्चो को पूरा करने के लिये कर्ज नहीं ले सकती है। कर्ज उन्हीं कार्यो के लिये लिया जा सकता है जिनसे राजस्व आय में वृद्धि होगी। राजस्व आय से राजस्व खर्चे ही पूरे किये जाते हैं। विकासात्मक

शेष पृष्ठ 8 पर.....

❖ ग्रामीण विकास, मनरेगा, पीडीएस, जल जीवन और खादों पर केंद्रीय बजट में हुई कटौती से प्रदेश का कर्जभार और बढ़ेगा

❖ प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है कि एक लाख करोड़ से भी अधिक का धन कहां खर्च हुआ

मुकेश अग्निहोत्री का ब्यान

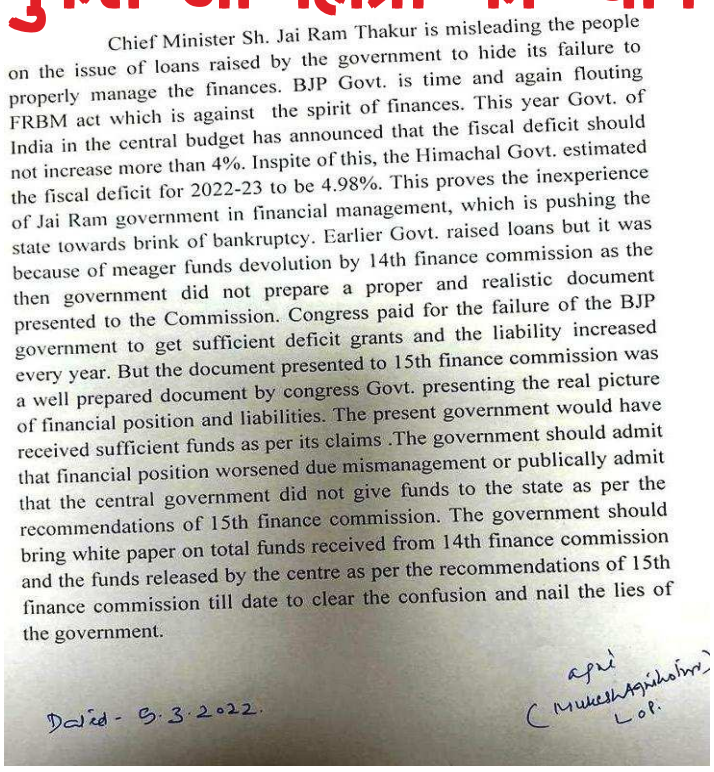

Chief Minister Sh. Jai Ram Thakur is misleading the people on the issue of loans raised by the government to hide its failure to properly manage the finances. BJP Govt. is time and again flouting FRBM act which is against the spirit of finances. This year Govt. of India in the central budget has announced that the fiscal deficit should not increase more than 4%. Inspite of this, the Himachal Govt. estimated the fiscal deficit for 2022-23 to be 4.98%. This proves the inexperience of Jai Ram government in financial management, which is pushing the state towards brink of bankruptcy. Earlier Govt. raised loans but it was because of meager funds devolution by 14th finance commission as the then government did not prepare a proper and realistic document presented to the Commission. Congress paid for the failure of the BJP government to get sufficient deficit grants and the liability increased every year. But the document presented to 15th finance commission was a well prepared document by congress Govt. presenting the real picture of financial position and liabilities. The present government would have received sufficient funds as per its claims .The government should admit that financial position worsened due mismanagement or publically admit that the central government did not give funds to the state as per the recommendations of 15th finance commission. The government should bring white paper on total funds received from 14th finance commission and the funds released by the centre as per the recommendations of 15th finance commission till date to clear the confusion and nail the lies of the government.

Dated - 5.3.2022.

क्या प्रदेश के बढ़ते कर्ज के लिए सरकार की उद्योग नीति भी जिम्मेदार है

शिमला/शैल। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा करीब 14 लाख को पहुंच चुका है। इसका अर्थ है कि प्रदेश का हर पांचवा व्यक्ति बेरोजगार है। इस समय प्रदेश के सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों का आंकड़ा भी पांच लाख तक ही पहुंच पाया है। प्रदेश के निजी क्षेत्र ने जितना रोजगार दिया है और उससे सरकार को जो राजस्व मिल रहा है यदि उसे निजी क्षेत्र को दी गयी सब्सिडी और अन्य आर्थिक लाभों के साथ मिलाकर आंकलित किया जाये तो शायद आर्थिक सहायता पर अदा किया जा रहा ब्याज उससे मिल रहे राजस्व से कहीं अधिक बढ़ जायेगा। यही नहीं निजी क्षेत्र की सहायता के लिए स्थापित किए गए संस्थान वित्त निगम, खादी बोर्ड और एसआईडीसी आदि आज किस हालत को पहुंच चुके हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की उद्योग नीतियां कितनी सफल और प्रसांगिक रही हैं। निजी क्षेत्र से इस संबंध में जुड़े आंकड़े कैग रिपोर्टो में उपलब्ध हैं। इसका एक उदाहरण यहां काफी होगा कि 1990 में जब बसपा परियोजना जेपी उद्योग को बिजली बोर्ड से लेकर दी गई तब उस पर बिजली बोर्ड का 16 करोड़ निवेश हो चुका था। इस निवेश को जेपी उद्योग ने ब्याज सहित वापस करना था। जब यह रकम 92 करोड़ को पहुंच गई तब इसे यह कहकर जेपी उद्योग को माफ कर दिया गया कि यदि इसे वसूला जाएगा तो जेपी बिजली के दाम बढ़ा देगा। इस पर कैग ने कई बार आपत्तियां दर्ज की हैं। जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। इसी सरकार के कार्यकाल में हाइड्रो कालेज के निर्माण में 92 करोड़ की ऑफर देने वाले टेंडर को नजरअंदाज करके 100 करोड़ की ऑफर वाले को काम दे दिया गया। स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली वर्दियों की खरीद में हुए घोटाले की चर्चा कई दिन तक पिछली सरकार के कार्यकाल में विधानसभा में भी रही थी। इसकी जांच के बाद आपूर्तिकर्ता फर्मो को ब्लैक लिस्ट करके करोड़ों का जुर्माना भी वसूला गया था। जिसे माफ कर दिए जाने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के शिक्षा विभाग के आग्रह को इस सरकार ने क्यों अस्वीकार कर दिया कोई नहीं जानता।

इस समय जब विपक्ष सरकार से कर्जो और केंद्रीय सहायता पर श्वेत पत्र की मांग कर रहा है तब इन सवालों का उठाया जाना ज्यादा प्रसांगिक हो जाता है। क्योंकि यदि सरकार यह श्वेत पत्र जारी करती है तब भी और यदि नहीं करती है तब भी प्रदेश के बढ़ते कर्जो पर एक बहस तो अवश्य आयेगी। जनता यह सवाल भी अवश्य पूछेगी

शेष पृष्ठ 8 पर.....

देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर है: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है और उन्हें भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने की

जरूरत है। उनका ज्ञान, क्षमता और तकनीक को देश और समाज की भलाई के लिए उन्हें इस तरह के कार्य करने चाहिए, जो समाज में उदाहरण बने और उन्हें स्वयं इसका एहसास हो, तभी उनके द्वारा अर्जित डिग्री महत्वपूर्ण साबित होगी।

राज्यपाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना के दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम समाज को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते और समाज के बिना हम सब अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि डिग्रीधारकों को यह समझना चाहिए कि जो भी सफलता हासिल की है वह समाज के सहयोग से ही संभव हुई है। उन्होंने कहा कि आईआईटी स्नातक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और समाज उनकी तरफ आशा से देख रहा है।

उन्होंने कहा कि डिग्री का सीमित अर्थ है। लेकिन अगर हम समाज के भीतर जाएं तब हमें इसकी प्रासंगिकता समझ आती है। समाज ने हमें हर कदम पर प्रोत्साहित किया है और भविष्य की चुनौतियों का सामना समाज के योगदान के बिना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए परिवर्तन पर बल दे रही है और इस शिक्षा नीति के माध्यम से राष्ट्र को नई गति मिलेगी।

इस अवसर पर केन्द्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है। उन्होंने स्नातकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के आगामी 25 वर्ष सभी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम इस अवधि के साक्षी बनेंगे। आज समाज सूचना प्रौद्योगिकी की ओर शीघ्रता से बढ़ रहा है और सभी क्षेत्र प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया जैसी पहल इसी पर ही आधारित है।

उन्होंने कहा कि आज के युग में सभी को किसी न किसी प्रकार की डिजिटल जीवन शैली अपनानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि महामारी के उपरान्त जिस युग में हमने कदम रखा है, वहां पर सभी को किसी न किसी प्रकार से तकनीक से जुड़ना पड़ेगा।

इससे पूर्व, आईआईआईटी ऊना सीनेट के निदेशक एवं अध्यक्ष प्रोफेसर एस. सेल्वा कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया और संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ी।

आईआईआईटी ऊना के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष और भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय के सचिव के. संजय मूर्थी, गवर्निंग बॉडी तथा विभिन्न समितियों के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।

राज्यपाल ने की अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मण्डी में आयोजित सात दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले एवं त्यौहार अपने में अनूठे होते हैं और यह राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव की बहुमूल्य परम्पराओं को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक राज्य एवं राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष भर उत्सव एवं त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यह उत्सव हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और इन आयोजनों से हमारे मन में कभी भी नकारात्मकता का प्रवेश नहीं हो पाता। साथ ही हमारा उत्साह भी कभी क्षीण नहीं होता। उन्होंने कहा कि यहां के ऊंचे पर्वतों की भांति प्रदेश के लोगों का हृदय भी विशाल है और हिमाचल अपने स्नेहपूर्ण आतिथ्य-सत्कार के लिए जाना जाता है। यहां के लोगों की देवी-देवताओं में अटूट आस्था के कारण ही इस देवभूमि की महता और भी बढ़ जाती है।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि संस्कृति और इसकी विरासत हमारी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने के साथ ही हमारे मूल्यों, आस्था और आकांक्षाओं को प्रदर्शित एवं आकार भी प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि मेले और त्यौहार लोगों में नव उर्जा का संचार करते हैं और हमें इनमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने राजदेव माधोराय के मन्दिर में पूजा-अर्चना की और इस अवसर पर आयोजित जलेब में शामिल हुए। उन्होंने सामूहिक भोज में भी भाग लिया।

अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने राज्यपाल का स्वागत एवं सम्मान किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पहली बार मेले में सात सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की गई हैं और मेले में 200 पंजीकृत देवता शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बजंतरियों के अनुदान एवं उनके राशन अनुदान तथा नजराना राशि में इस वर्ष आशातीत बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि भी बढ़ाई गई है। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

हिमाचल में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने में महिला किसानों का अनुकरणीय योगदान: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हिमाचल की किसान महिलाएं जिस उत्साह के साथ प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपना रही हैं, वह देश के लिए एक अनुकरणीय

उदाहरण और प्रेरणास्रोत है।

राज्यपाल सोलन जिले के नौणी में डॉ.वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में विभाग महिलाओं के लिए प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। यह कार्यशाला प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आयोजित की गई, जिसमें 800 से अधिक किसान महिलाओं ने भाग लिया।

राज्यपाल ने कहा कि किसान महिलाओं का योगदान प्रेरणादायक है और उनके योगदान से हिमाचल देश में प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बन कर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्राकृतिक खेती का श्रेय प्रदेश के किसानों को दिया है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश की ओर से आश्वासन दिया है कि राज्य में शीघ्र ही इस पद्धति को अपनाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इस दिशा में महिला किसानों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग की आवश्यकता होगी।

उन्होंने प्राकृतिक खेती को घर का चिकित्सक बताया क्योंकि प्राकृतिक खेती के उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। उन्होंने कहा कि यह पद्धति नई नहीं है और यह हमारी पारंपरिक प्रणाली रही है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि राज्य में 1.68 लाख किसान इससे जुड़े हैं और 55 प्रतिशत महिलाएं इस पद्धति से कार्य कर राज्य को नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत 25,000 एकड़ भूमि को लाया गया है।

डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वाणिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. परविंदर कौशल ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती में महिलाओं का अनुभव वास्तव में प्रेरक है, जो इस कृषि पद्धति को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के नकारात्मक परिणाम आए हैं परंतु प्राकृतिक खेती के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। उन्होंने किसानों से इसे पूरी तरह अपनाने का आहवान किया। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा किसानों और बागवानों के हित में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी।

कृषि सचिव राकेश कंवर ने कहा कि यह कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं को समर्पित है, क्योंकि हिमाचल में प्राकृतिक खेती की सफलता का वास्तविक श्रेय महिलाओं को ही जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने भी बजट में 50 हजार हेक्टेयर भूमि को इस कृषि पद्धति के अन्तर्गत लाने, 100 गांवों को प्राकृतिक खेती वाले गांव बनाने, 50 हजार किसानों का प्रमाणीकरण करने और प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बेचने के लिए राज्य के हर जिले में दुकानें बनाने का भी प्रस्ताव रखा हैं। उन्होंने कहा कि इस कृषि पद्धति को अपनाने से किसानों की आय में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश्वर चंदेल ने राज्यपाल का स्वागत किया और तीन दिवसीय कार्यशाला की विस्तृत जानकारी प्रदान दी।

इस मौके पर महिला किसानों ने अपने अनुभव भी साझा किए।

जिला सोलन के आत्मा परियोजना के निदेशक सुरेंद्र ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी, पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र शर्मा, कृषि वैज्ञानिकों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल ने रिट्रीट का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने परिवार के सदस्यों सहित शिमला जिले के छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास रिट्रीट

भवन का अवलोकन किया।

प्रवास के दौरान राज्यपाल ने रिट्रीट के रेजिडेंट स्टाफ से बातचीत की। कर्मचारियों ने उन्हें रिट्रीट में संचालित विभिन्न गतिविधियों के संबंध ा में जानकारी दी। राज्यपाल ने परिसर का भी दौरा किया।

इस अवसर पर राज्यपाल क्षेत्र के शांत वातावरण से बहुत प्रभावित हुए।इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया और राजभवन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी राज्यपाल के साथ थे।

केबीसी प्रतिभागी अरुणोदय ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचली टेलेंट मास्टर अरुणोदय शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से

भेंट की। टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति-13 के विद्यार्थी विशेष में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले अरूणोदय के साथ इस अवसर पर अरुणोदय के पिता जगदीश शर्मा और मां ममता पाल शर्मा भी उपस्थित थी।

राज्यपाल ने अरुणोदय को सम्मानित किया और केबीसी-13 के अनुभवों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि अरुणोदय हिमाचल का गौरव है तथा हमें उनकी सादगी और प्रतिभा पर गर्व है।

राज्यपाल ने अरुणोदय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी हाजिर जवाबी असाधारण है।

मुख्यमंत्री ने आरकेएमवी में छः करोड़ रुपये लागत से नव–निर्मित बी–ब्लॉक भवन का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) शिमला में छः करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बी–ब्लॉक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने छोटा राज्य होने के बावजूद विकास के मामले में देश के अन्य बड़े राज्यों का पथ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश सरकार प्रदेश के कुल बजट का लगभग 16 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय कर रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम का कोई और विकल्प नहीं है और आज के प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए।

उन्होंने महाविद्यालय के विज्ञान खंड के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपये प्रदान करने तथा शीघ्र तैयार होने वाले नए खंड में बहुउद्देशीय हॉल के लिए दो करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं को अपनी ऐच्छिक निधि से 51 हजार रुपये देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आरकेएमवी प्रदेश के प्रतिष्ठित कन्या महाविद्यालयों में से एक है। इस महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर चुकी गई छात्राओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने महाविद्यालय के विज्ञान खंड के जीर्णोद्धार और बहुउद्देशीय हॉल के लिए निधि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से महाविद्यालय के लिए नए छात्रावास भवन को निर्मित का आग्रह किया।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों की निर्बाध पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 8412 करोड़ रुपये बजट आबंटित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला के प्रधानाचार्य डॉ. नविंदू शर्मा ने मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए वर्ष 2022–23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

हिमाचल में भी मिशन रिपीट में सफल रहेगी भाजपा: जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत पर केन्द्रीय नेतृत्व विशेषतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच में से चार राज्यों में यह विशाल जीत केंद्र एवं भाजपा शासित राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति जनमत को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की जनता ने इन राज्यों की सरकारों और केन्द्रीय नेतृत्व के प्रति अपनी पूर्ण आस्था जताई है। उन्होंने कहा कि इससे विभाजनकारी तत्वों को एक बार पुनः यह सन्देश गया है कि देश की जनता एक मजबूत और सक्षम नेतृत्व चाहती है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इन राज्यों के चुनावों परिणामों से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में भी मिशन रिपीट में सफल रहेगी क्योंकि देश के साथ–साथ प्रदेश की जनता भी कांग्रेस पार्टी से निराश हो चुकी है और पांच राज्यों के आम चुनावों में लोगों ने कांग्रेस को पूर्ण रूप से नकार दिया है। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपने मंत्रीमंडलीय सहयोगियों, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और विधायकों के साथ शिमला के चक्कर स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय दीपकमल में खुशियां मनाई।

शहरी विकास मंत्री ने राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के गेयटी थियेटर में वस्तु मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

शहरी विकास मंत्री ने अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग से हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं और अपने परिवार की आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ ही पारम्परिक हिमाचली हस्तकला के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सभी व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस तरह की प्रदर्शनियों के माध्यम से बुनकरों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच उपलब्ध होता है। इस प्रदर्शनी में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकरों के उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है और दस्तकारों एवं बुनकरों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 15 हजार लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हथकरघा उद्योग को युवा वर्ग की पसंद बनाने के लिए विभिन्न डिजाइनर अग्रणी संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे हैं और उत्पादों को युवाओं की रूचि के अनुरूप बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। मूल हथकरघा उत्पादों में स्थानीय ऊन, याक वूल, अंगोरा वूल एवं मरीनो वूल का प्रयोग होता है, जोकि मंहगा धागा है।

उन्होंने कहा कि कुल्लू व किन्नौरी शॉल के डिजाइन को जीआई मार्क मिला है और प्रदेश सरकार अन्य उत्पादों को भी इसके अन्तर्गत लाने के लिए प्रयासरत है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम की प्रबन्ध निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि 8 मार्च से 14 मार्च, 2022 तक आयोजित इस प्रदर्शनी में वही बुनकर पात्र हैं, जिनके पास केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत हैंडलूम मार्क है या उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है।

इस सात दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 25 बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने का अवसर उपलब्ध करवाया गया है। योजना के अन्तर्गत पात्र बुनकरों को 500 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता और 4 हजार रुपये यात्रा भत्ता एवं सामान ढुलाई के रूप में दिया जाएगा।

सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य करें पंचायत प्रतिनिधि:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आम आदमी को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया है। वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक संस्था द्वारा आयोजित प्राइड ऑफ हिमाचल वेबिनार को संबोधित कर रहे थे।

इस कार्यक्रम में शिमला, सोलन और सिरमौर जिला की 429 पंचायतों की महिला प्रधानों और विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ–साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता और अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्रियता सराहनीय है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में महिलाओं के समग्र विकास और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक नवोन्मेषी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की।

वेबिनार के आयोजक अक्षय वर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. डेज़ी ठाकुर, रशिम धर सूद, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका, वरिष्ठ अधिकारी नीरज चांदला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने आईटीआई शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलेट स्कूल का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। ड्रोन आधुनिक युग की तकनीक है, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित कर इसे रोज़मर्रा के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का उद्घाटन करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि ड्रोन एक नवाचार तकनीक है, जिसे फसलों पर निगरानी रखने के अतिरिक्त कीटनाशक के छिड़काव आदि के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राज्य सरकारों को ड्रोन तकनीक को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ड्रोन तकनीक का उपयोग भूमि की हदबन्दी तथा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में दस्तावेज तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि यह न केवल किफायती है, बल्कि यह समय की बचत भी करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ड्रोन तकनीक युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और युवाओं को इस तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने मुख्यमंत्री का उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करते हुए कहा कि यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह ड्रोन पायलट स्कूल क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार तथा स्वरोज़गार सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करने में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने क्षेत्र की विकासात्मक मांगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर, पूर्व विधायक सुरेन्द्र काकू, जिला भाजपा अध्यक्ष चन्द्र भूषण नाग, जिला परिषद् अध्यक्ष रमेश बराड़, निदेशक तकनीकी शिक्षा विवेक चन्देल, उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिन्दल, पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल चन्द शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रशासनिक सेवाएं प्रारम्भिक परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र में संशोधन 14 मार्च तक

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय लोक सेवा आयोग प्रशासनिक सेवाएं (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2022, जिसमें भारतीय वन सेवाएं (प्रारम्भिक) परीक्षा 2022 भी शामिल है, पूरे देश में 5 जून, 2022 को आयोजित कर रहा है। आयोग ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इस परीक्षा के लिए दो अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र धर्मशाला और मण्डी में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके दृष्टिगत आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रशासनिक सेवाएं (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2022 के आवेदक अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र चुनने के लिए एक बार पुनः मौका दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पसंद का केन्द्र चुन सकें।

उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदकों से दो चरणों में उनकी पसंद मांगी जायेगा, जिसमें प्रथम चरण 3 से 7 मार्च, 2022 तथा दूसरे चरण में 10 से 14 मार्च, 2022 को सायं 6 बजे तक आवेदक अपने केन्द्र के बारे में संशोधित पसंद https://upsconline. nic.in पर दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई आवेदक केन्द्र में बदलाव नहीं चाहता है तो वह पहले भरे गए केन्द्र पर ही परीक्षा दे सकेगा। परीक्षा केन्द्र में बदलाव के लिए पुनः आवेदन के उपरांत पहले आओ पहले पाओ आधार पर केन्द्र आवंटित किए जाएंगे। एक बार आवंटित केन्द्र की क्षमता पूर्ण हो जाने पर उसे फ्रीज कर दिया जाएगा और आवेदकों को शेष केन्द्रों में से किसी एक को चुनना होगा।

उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए पूर्व में जारी अन्य दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

चुनाव के बाद उठते सवाल

चुनाव परिणाम आने के बाद चार राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मणिपुर और गोवा में भाजपा और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें बनी है। इन चुनावों के परिणामों को लेकर केवल एग्जिट पोल ही सही साबित हुये हैं। अन्यसभी के आकलन गलत निकले हैं। इस स्वीकारोक्ति के साथ भाजपा और आप को बधाई। लेकिन जिस तरह के परिणाम सामने आये हैं और अंतिम चरण के मतदान के बाद जो कुछ भी घटा है उससे कुछ ऐसे सवाल भी उभरे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। भाजपा की इससे पहले भी चार राज्यों में सरकारें थी जो अब भी बहाल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 के मुकाबले इस बार 48 सीटों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में पार्टी तो जीत गयी लेकिन उसका मुख्यमंत्री हार गया। गोवा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला अन्य के सहयोग से सरकार बना दी जायेगी। यहां पर भी मुख्यमंत्री का घोषित चेहरा चुनाव हार गया है। मणिपुर में चुनावों के दौरान शांति बनाये रखने के लिये वहां के एक प्रतिबन्धित संगठन को सरकार द्वारा 15 करोड़ दिये जाने का भी तथ्य चर्चा में आ गया है। उत्तर प्रदेश में भी ईवीएम मशीनों का काण्ड मतदान के अंतिम चरण के बाद सामने आया और चुनाव आयोग को तीन अधिकारी निलंबित करने पड़े हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा की भारी जीत हो रही थी तो फिर ईवीएम काण्ड क्यों घटा? बरेली में कूड़े की गाड़ी में मतपत्र और मोहरें क्यों मिली? कानपुर में डाले गये कुल मतों से गिने गये मतों की संख्या क्यों बढ़ी? सर्वोच्च न्यायालय में वीवीपैट का दायरा बढ़ाने की मांग को लेकर आयी याचिका की सुनवाई के लिये पहले शीर्ष अदालत तैयार हो गयी लेकिन चुनाव आयोग का जवाब आने के बाद इस आग्रह को अस्वीकार क्यों कर दिया गया? आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अतिरिक्त उत्तराखंड और गोवा में भी सरकार बनाने के दावों के साथ चुनाव लड़ा था। वहां पर उसका प्रदर्शन खराब क्यों रहा? उत्तर प्रदेश में भी आपको कुछ नहीं मिला क्यों? चुनाव परिणामों के मुताबिक चार राज्यों में जनता ने भाजपा की नीतियों पर मोहर लगायी है। तो फिर उसी गणित से पंजाब में भाजपा – अमरेंद्र गठबंधन को जनता ने क्यों नकार दिया है? यह ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में जवाब मांगेंगे। ममता की टीएमसी ने भी गोवा में चुनाव लड़ा था सरकार बनाने का दावा किया था। उसका प्रदर्शन भी सफल क्यों नहीं रहा? उत्तर प्रदेश में चुनाव के बसपा और भाजपा में तीन सौ करोड़ का सौदा होने की जानकारी एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से सामने आयी थी। चुनाव आयोग इस पर खामोश क्यों रहा?

सरकारों की सत्ता में वापसी जनता द्वारा उसकी नीतियों का स्वीकार माना जाता है। ऐसे में आज महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने के जो मुद्दे हैं उन पर अब जनता को कोई भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं रह जाता है। जिस किसान ने कृषि कानूनों से आहत होकर तेरह माह तक आंदोलन किया और सात सौ किसानों के प्राणों की आहुति दी है उसे भी अब सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का सवाल उठाने का अधिकार नहीं रह जाता है। कांग्रेस और अन्य दलों ने अपनी हार के कारणों का खुलासा अभी तक जनता के सामने नहीं रखा है। इसलिए उन पर अभी कोई चर्चा करना तो ज्यादा प्रसांगिक नहीं होगा। कांग्रेस नेतृत्व रफाल, पैगासैस और सार्वजनिक सम्पतियों, संस्थानों को मौद्रीकरण विनिवेश के नाम पर निजी क्षेत्र को सौंपने का सच जनता के सामने रख दिया है यही उसकी जिम्मेदारी थी। इस मौद्रीकरण और विनिवेश के कारण महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ती रही है। आगे भी बढ़ेगी क्योंकि जब समाज के एक वर्ग को कुछ नि:शुल्क दिया जाता है तो उस खर्च को पूरा करने के लिए या तो जनता पर सरकार टैक्स लगाती है या कर्ज लेती हैं क्योंकि सरकार की आय का और कोई साधन नहीं होता है। दादा को पैन्शन देकर बेरोजगार पोते को रोजगार नहीं मिलता है और न ही घर का खर्च चल रहा पिता इस पैन्शन से महंगाई से लड़ पायेगा। आज जनता को यह समझने की जरूरत है क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है उसे जनता ने ही भोगना है चाहे वह किसी की भी समर्थक हो

भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक हब बनाना

वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया

डॉ.के.सी.गुम्मागोलमथ
निदेशक
एमएएनएजीई
(राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान),
हैदराबाद

ज्यादातर वर्षा सिंचित भूमि में उगाये जाने वाले मोटे अनाजों को जलवायु – अनुकूल स्मार्ट फसल कहा जा सकता है। भारत में इन फसलों की खेती विशेष रूप से अर्ध – शुष्क जलवायु की परिस्थितियों वाले क्षेत्रों तक सीमित है। ये फसलें तापमान, नमी और विभिन्न इनपुट परिस्थितियों के उतार – चढ़ाव को सहन कर सकती हैं एवं शुष्क भूमि के लाखों किसानों को भोजन की आपूर्ति करने के साथ पशुओं को चारा भी प्रदान करती हैं। औद्योगिक देशों में इनका उपयोग पीने योग्य अल्कोहल और स्टार्च उत्पादन के एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है।

भारतीय उपमहाद्वीप में, मोटे अनाजों को पोषक तत्वों के भंडार के रूप में एक उत्कृष्ट अनाज माना जाता है। मोटे अनाजों की सभी किस्मों में उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, ये ग्लूटेन – मुक्त होते हैं तथा इनसे एलर्जी भी नहीं होती है। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता – मांग और आहार – पैटर्न में धीरे – धीरे बदलाव आ रहा है और हाल के दिनों में इन मोटे अनाजों के लिए बाजार की संभावना भी बन रही है। उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता के कारण मूल्य वर्धित उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

भारत में मोटे अनाजों की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में की जाती है। राजस्थान (बाजरा क्षेत्र का 87 प्रतिशत), महाराष्ट्र (ज्वार क्षेत्र का 75 प्रतिशत) और कर्नाटक (रागी क्षेत्र का 54 प्रतिशत और बाजरा क्षेत्र का 32 प्रतिशत)।

एफएओ के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में, मोटे अनाजों की खेती का क्षेत्रफल औसतन 108 लाख हेक्टेयर है और 2000 तथा 2019 के बीच इसमें 27 लाख हेक्टेयर की कमी आने की जानकारी मिली है। विश्लेषण से पता चलता है कि मोटे अनाजों के क्षेत्रफल में 2000 से 2019 के बीच 2.25 प्रतिशत की दर से कमी दर्ज की गयी है, जबकि उत्पादन में वृद्धि केवल 0.08 प्रतिशत रही है। हालांकि, उत्पादकता 2.38 प्रतिशत सकारात्मक सीएजीआर दर्शाती है।

विश्व स्तर पर मोटे अनाजों का बाजार 2019 में 9 बिलियन डॉलर था और इसके 12.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वैश्विक मांग में 38 प्रतिशत हिस्से का योगदान देता है। भारत और विश्व स्तर पर कोविड – 19 महामारी के दौरान पोषक तत्वों से युक्त भोजन की मांग में वृद्धि के कारण मोटे अनाजों और मोटे अनाजों के उत्पादों को बढ़ावा मिला है।

मोटे अनाजों का निर्यात किये जाने वाले प्रमुख देशों में नेपाल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ट्यूनीशिया, श्रीलंका, यमन गणराज्य, लीबिया, नामीबिया और मोरक्को हैं। डीजीसीआईएस के अनुसार, वर्ष 2019 – 20 में भारत से 8 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाजों का निर्यात किया गया था, जिनकी कीमत 205.2 करोड़ रुपये (28.75 मिलियन डॉलर) थी।

मोटे अनाजों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता रहती है, जो मुख्यत: आपूर्ति की मात्रा से निर्धारित होती हैं और आमतौर पर अन्य प्रमुख फसलों की कीमतों से अप्रभावित रहती हैं। हालांकि, वैकल्पिक मूल्य श्रृंखला के विकास के साथ कीमतों में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

नीति को प्रोत्साहन और कार्य योजना

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने (2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष' के रूप में घोषित करने के लिए बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के साथ भारत द्वारा प्रस्तुत किये गये एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इस पृष्ठभूमि में, मोटे अनाज के निर्यात में दुनिया का अग्रणी देश बनने के लिए भारत द्वारा एक कार्य योजना शुरू किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य योजना में निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है:

1. मोटे अनाजों की उत्पादन प्रणालियों में अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना और इसे लागत – प्रभावी बनाना।
2. कृषि – पारिस्थितिकी की विभिन्न श्रृंखलाओं के तहत मोटे अनाजों की खेती को अत्यधिक लाभप्रद बनाना।
3. मोटे अनाजों को पोषण – युक्त भोजन के रूप में प्रोत्साहन देना, पीने योग्य और औद्योगिक अल्कोहल, स्टार्च आदि के उत्पादन के लिए इन्हें कच्चे माल के रूप में बढ़ावा देना तथा मोटे अनाजों के डंठल सहित अन्य उत्पादों का प्रचार – प्रसार करना।
4. कुशल मूल्य श्रृंखला के लिए उत्पादन – क्षेत्र के आसपास प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना करना। एफपीओ द्वारा दी गयी सुविधा से संचालित व समुदाय के स्वामित्व वाली प्रसंस्करण इकाइयों को बड़े पैमाने का लाभ मिल सकता है।
5. पोषण संबंधी लाभों के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता को बढ़ाने के लिये कॉरपोरेट और स्टार्ट – अप, खाद्य गुणवत्ता/सुरक्षा मानकों एवं बेहतर ब्रांडिंग के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल:

हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन दिशानिर्देशों (एनएफएसएम) के माध्यम से, भारत सरकार ने मोटे अनाजों के लिए महत्वपूर्ण 14 राज्यों के 212 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन/वितरण, क्षेत्र – स्तर पर प्रदर्शन, प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रसंस्करण क्लस्टर और अनुसंधान सहायता के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) ने मोटे अनाजों के उद्यमियों, अनाजों के प्राथमिक प्रसंस्करण और एफपीओ को मशीनरी उपलब्ध कराने आदि के लिए निवेश को बढ़ावा दिया है। 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) पहल के तहत मोटे अनाजों के लिए 27 जिलों की पहचान की गयी है, जिन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। भारत में लगभग 80 एफपीओ हैं, जो ज्वार और मोटे अनाजों का उत्पादन कर रहे हैं। एफपीओ किसानों को एकत्रित करने और उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक सक्षम संस्था के रूप में कार्य कर सकते हैं।

मोटे अनाजों और इनके उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की संभावना और पोषण – अनाज के रूप में मोटे अनाज क्षेत्र के विकास पर सरकार के विशेष जोर को ध्यान में रखते हुए, एपीडा आईसीएआर – आईआईएमआर एवं राष्ट्रीय पोषण संस्थान, सीएसआईआर – सीएफटीआरआई, एफपीओ जैसे अन्य हितधारकों के साथ एक रणनीति तैयार कर रहा है, ताकि मोटे अनाजों और मोटे अनाजों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पांच साल की एक भावी कार्य – योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। निर्यात अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास पर आधारित योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा सकती है।

मोटे अनाजों की उपयोग – अवधि (शेल्फ लाइफ) बढ़ाने, उत्पादन में वृद्धि करने, पैकेजिंग लाइन को आधुनिक बनाने, प्रयोगशाला उपकरण और नमूनों के परीक्षण जैसी कमियों को दूर करने आदि के लिए एपीडा प्रसंस्करण सुविधाओं में सहायता प्रदान करेगा।

केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन, घरेलू खपत बढ़ाने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों की ब्रांडिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। कर्नाटक, इन सुपर फूड्स के उत्पादन में विविधता लाने और बढ़ावा देने के लिए 2017 से रायथा सिरी योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन (2 हेक्टेयर तक सीमित) दे रहा है। अन्य राज्य, इस योजना का अनुसरण कर सकते हैं।

उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि भारत में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल नीति मौजूद है। अनाज की बढ़ती मांग और कृषि – पारिस्थितिकी के तुलनात्मक लाभ के साथ, भारत मोटे अनाजों की खेती, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात में विश्व स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में उभर सकता है। फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन, घरेलू खपत बढ़ाने और मोटे अनाजों के उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने आदि के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

कृषि वानिकी और लकड़ी आधारित उद्योगों का एकीकृत विकास – कार्बन-निरपेक्ष अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह

आर. के. सपरा
आई.एफ.एस. (सेवानिवृत्त)
सदस्य, एसईएसी
राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण

कार्बन – निरपेक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कृषि वानिकी और निजी वानिकी

भारत सरकार ने हाल ही में पेश वित वर्ष 2022-23 के बजट में भारत को 'कार्बन-निरपेक्ष अर्थव्यवस्था' बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 'कृषि वानिकी और निजी वानिकी' का उपयोग उपयुक्त माध्यमों के रूप में किया है। कृषि वानिकी के तहत ऐसी लघु चक्रीय वृक्ष फसलें या शॉर्ट रोटेशन पेड़ लगाए जाते हैं जो आम तौर पर किसानों द्वारा लगाए जाते हैं। वहीं, दूसरी ओर निजी वानिकी के तहत ऐसी मध्यम एवं दीर्घ चक्रीय वृक्ष फसलें या मीडियम एवं लॉन्ग रोटेशन पेड़ लगाए जाते हैं जो आम तौर पर बागान कंपनियों अथवा व्यक्तियों द्वारा अपनी-अपनी भूमि पर लगाए जाते हैं। भारत कृषि वानिकी के माध्यम से छोटे आकार की लकड़ी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के काफी करीब पहुंच गया है, लेकिन वनों से बड़े आकार की लकड़ी बेहद कम मिलने के कारण भारत अब भी आयातित इमारती लकड़ी या टिम्बर पर बहुत अधिक निर्भर है और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसानों द्वारा इसका उत्पादन करना उनके बस की बात नहीं है। निजी वानिकी को प्रोत्साहित करने वाली भारत सरकार की हालिया पहल से बड़े आकार की लकड़ी के स्थानीय उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत भारत ने यूएनएफसीसीसी के पेरिस समझौते के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 अरब टन का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कृषि वानिकी और निजी वानिकी के तहत वृक्षारोपण से न केवल कार्बन पृथक हो जाता है, बल्कि उनकी लकड़ी से तैयार लकड़ी उत्पाद या काष्ठ उत्पाद भी अपना अस्तित्व बरकरार रहने तक सदैव कार्बन का संचय करते रहते हैं। कृषि वानिकी एवं निजी वानिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस कदम उठाने से एनडीसी के तहत तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और इसके साथ ही देश के 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वनों एवं वृक्षों से आच्छादित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने को भी नई गति मिलेगी, जैसा कि वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में परिकल्पित है।

2.0 कृषि वानिकी की वर्तमान स्थिति

सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध और अस्सी के दशक के दौरान कुछ राज्यों ने स्व-वित्तपोषित और बाह्य सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाओं को लागू किया था जिनमें कृषि वानिकी का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लकड़ी आधारित उद्योग ने किसानों के साथ सीधा संपर्क सुनिश्चित करके कच्चे माल की अपनी मांग को पूरा करना शुरू कर दिया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स (आईएस एफआर) के अनुसार कृषि वानिकी पर ध्यान केंद्रित करने की बदौलत 'टीओएफ (वनों के बाहर पेड़)' के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र वर्ष 2001 के 5.6% से बढ़कर वर्ष 2021 में भारत के समग्र भौगोलिक क्षेत्र का 8.9% हो गया और वार्षिक लकड़ी उत्पादन 69 से बढ़कर 85 मिलियन घन मीटर हो गया। कृषि वानिकी वृक्षारोपण के तहत आने वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से लकड़ी का उत्पादन होगा और इन क्षेत्रों का अस्सी से नब्बे प्रतिशत हिस्सा सदैव हरा-भरा रहेगा जिससे कार्बन को पृथक करने में मदद मिलेगी। चूंकि वन क्षेत्रों से इमारती लकड़ी या टिम्बर की उपलब्धता कम हो गई और खेतों से मिलने वाली लकड़ी पूरी तरह से वनों से मिलने वाली इमारती लकड़ी का विकल्प नहीं बन सकी, इसलिए सरकार ने नब्बे के दशक में इमारती लकड़ी या टिम्बर के आयात को उदार बना दिया। भारत में लकड़ी और लकड़ी आधारित उत्पादों के सतत व्यापार (2021) के अनुसार, 15 मिलियन घन मीटर गोल लकड़ी का आयात किया गया जो कि लगभग 450 अरब रुपये मूल्य के लकड़ी और लकड़ी या काष्ठ उत्पादों के बराबर था।

कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए कुछ कंपनियों जैसे कि विमको सीडलिंग्स लिमिटेड और आईटीसी, भद्राचलम पेपरबोर्ड लिमिटेड, इत्यादि ने 1980 के दशक में गुणवत्तापूर्ण या बेहतरीन पौधों, वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग और सुनिश्चित वापस खरीद (बायबैक) व्यवस्था के जरिए वृक्ष फसल या पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया। इन मॉडलों से लकड़ी आधारित उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। इसी तरह हरियाणा राज्य, जिसे देश की 'प्लाईवुड राजधानी' के रूप में जाना जाता है, में स्थित लकड़ी आधारित उद्योगों का यमुनानगर क्लस्टर वर्तमान में देश के लगभग 40 प्रतिशत प्लाईवुड के उत्पादन की क्षमता रखता है। यह क्लस्टर कृषि लकड़ी या खेतों से मिलने वाली लकड़ी के लिए सबसे बड़ा बाजार है और इसने किसानों, मजदूरों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों सहित सभी हितधारकों को लाभान्वित किया है। अत: कृषि वानिकी और लकड़ी आधारित उद्योग के एकीकृत विकास से लकड़ी या काष्ठ क्षेत्र का तेज विकास सुनिश्चित होगा।

कृषि वानिकी क्षेत्र के विकास में आनेवाली समस्याएं और आवश्यक कार्रवाई

किसान: किसानों को मुख्य रूप से पेड़ों की कटाई एवं लकड़ी के अंतर-राज्यीय परिवहन में आने वाली बाधाओं, नर्सरी में खराब गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों से वंचित विस्तार संबंधी अपर्याप्त सेवाएं, कटाई की लंबी अवधि के कारण लकड़ी की कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव, और कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले, वृक्षारोपण के पंजीकरण, पेड़ों की कटाई और लकड़ी की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करके पेड़ों की कटाई और लकड़ी के अंतर-राज्यीय परिवहन के नियमों में अखिल भारतीय स्तर पर संशोधन किया जाना चाहिए। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए निजी नर्सरी को मान्यता प्रदान करने से संबंधित एक रूपरेखा तय होनी चाहिए। तीसरा, प्रभावी नेटवर्किंग से लैस लकड़ी के बाजार स्थापित किए जा सकते हैं। चौथा, आईटीसी, विमको आदि के सहजीवी मॉडल को बढ़ावा दिया जा सकता है। पांचवां, कार्बन संबंधी व्यापार को सुगम बनाया जा सकता है और छठा, अनुसंधान एवं विकास की दिशा में गहन प्रयास किए जा सकते हैं।

लकड़ी आधारित उद्योग: लकड़ी आधारित उद्योग मुख्य रूप से जटिल लाइसेंसिंग नीति के कारण प्रभावित होते हैं क्योंकि नए लाइसेंस/इकाइयों के विस्तार से संबंधित आदेश लकड़ी की बढ़ी हुई उपलब्धता, कृषि उपज के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली महंगी कृषि लकड़ी या खेत से मिलने वाली लकड़ी, गैर-प्रमाणित कृषि लकड़ी और आयातित लकड़ी के उत्पादों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बारे में आकलन करने के बाद ही जारी किए जाते हैं। उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले, लकड़ी आधारित उद्योग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बराबर का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा, दीर्घकालिक अवधि में ठोस लकड़ी की मांग को कम करने के लिए मिश्रित लकड़ी के पैनलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरा, लकड़ी आधारित उद्योग के उन्नयन को सुगम बनाया जा सकता है और चौथा, कुशल श्रमशक्ति के लिए व्यापक प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सकती है।

विजन-2047 (अमृत काल) और अनुमानित लाभ

अमृत काल (25 वर्ष की अवधि) के दौरान निम्नलिखित विजन-2047 प्रस्तावित है:

अतिरिक्त रूप से, 10 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 3% हिस्सा) को वृक्षारोपण के तहत लाया जा सकता है, जिसमें से पांच मिलियन हेक्टेयर भूमि में शॉर्ट रोटेशन वाले पेड़ लगाए जा सकते हैं और अन्य पांच मिलियन हेक्टेयर भूमि में मीडियम और लॉन्ग रोटेशन वाले पेड़ लगाए जा सकते हैं।

लकड़ी आधारित उद्योगों के 100 क्लस्टरों का विकास।

भारत को 'लकड़ी के उत्पादों का आयात करने वाला से लकड़ी के उत्पादों का निर्यात करने वाला' देश बनाना।

अनुमानित लाभ: उपरोक्त योजना से निम्नलिखित अनुमानित लाभ होंगे:

कृषि वानिकी: पॉपलर, यूकेलिप्टस, बाकेन आदि जैसे शॉर्ट रोटेशन वाले पेड़ों के वृक्षारोपण से लगभग 420 बिलियन रुपये मूल्य की लगभग 100 मिलियन क्यूबिक मीटर लकड़ी का वार्षिक उत्पादन होगा और इससे लगभग 371 मिलियन कार्य दिवसों के बराबर का रोजगार पैदा होगा यहअनुमान है।

निजी वानिकी: गम्हार, कदम, सिल्वर ओक, किकर जैसे मीडियम रोटेशन वाले पेड़ों और सागौन एवं शीशम जैसे लॉन्ग रोटेशन वाले पेड़ों के वृक्षारोपण से लगभग 645 बिलियन रुपये मूल्य की लगभग 37 मिलियन क्यूबिक मीटर लकड़ी का वार्षिक उत्पादन होगा और इससे लगभग 147 मिलियन कार्य दिवसों के बराबर का रोजगार पैदा होगा।

भारत काष्ठ उत्पादों का एक निर्यातक देश बनेगा।

नीतिगत पहल

काष्ठ क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल करने की आवश्यकता है:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय काष्ठ मिशन की स्थापना, वनों के बाहर के पेड़ों (टीओएफ) के बारे में कानून बनाना, कृषि लकड़ी या खेत से मिलने वाली लकड़ी पर निर्भर लकड़ी आधारित उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाना है।

वित मंत्रालय द्वारा खेत से मिलने वाली लकड़ी से निर्मित काष्ठ उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर को कम करना, रियायती ऋण, पूंजीगत सब्सिडी और कर रियायतों जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके निजी वानिकी को व्यापक रूप से बढ़ावा देना है।

लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात और आयात नीति की समीक्षा करना जोकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देखेगा।

खेत से मिलने वाली लकड़ी के संबंध में स्वैच्छिक प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना और अवैध लकड़ी के आयात को विनियमित करना।

यह खुशी की बात है कि कृषि वानिकी क्षेत्र के विकास से संबंधित पहल और सुधारों की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर से की जा रही है। इन पहल के कार्यान्वयन से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, किसानों की आय में वृद्धि होगी, विभिन्न हितधारकों के लिए व्यापार के अवसर बेहतर होंगे, विदेशी मुद्रा की कमाई सहित सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। खेत से मिलने वाली लकड़ी जहां काफी हद तक लकड़ी आधारित उद्योग की मांगों को पूरा करेगी, वहीं वन क्षेत्र देश की इकोलॉजी से जुड़ी जरूरतों के साथ-साथ जंगलों में और उसके आस-पास रहने वाले परिवारों की आजीविका संबंधी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होंगे।

उद्यमियों को निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए हिमाचल को देश का सबसे पसंदीदा राज्य बनाने के लिए सरकार कृतसंकल्पः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार उद्यमियों को निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे पसंदीदा राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही जिसका विषय विकास की गति को पुनः प्राप्त करना, रखा गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग एवं उद्योगपतियों ने कोविड महामारी के दौरान बहुत ही सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने यह सुनिश्चित किया कि वे इस चुनौतिपूर्ण समय से न केवल स्वयं उबरेंगे बल्कि जरूरतमंद लोगों तक राहत प्रदान करने में भी अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं प्रारम्भ की हैं लेकिन महामारी

ने इन योजनाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य में दो ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग सुधारने में भी सफल रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि व्यापार से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं अथवा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उदारीकरण के वर्तमान दौर में प्रदेश सरकार का यह प्रयास रहा है कि व्यापार में न्यूनतम हस्तक्षेप हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के लिए 261 करोड़ रुपये से स्थापित होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रही हैं और इसकी स्थापना के लिए सोलन जिला के नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना से प्रदेश में चार हजार से पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का टर्नओवर होगा और अनुमानित दस हजार लोगों को इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार की बल्क ड्रग पार्क योजना के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है और ऊना जिला में 1405 एकड़ भूमि पर इस पार्क को स्थापित करने के लिए 1190 करोड़ रुपये की परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 8000 करोड़ रुपये के निवेश से लगभग 50000 करोड़ रुपये का टर्नओवर सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क से राज्य के लगभग 15000 युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेल सम्पर्क स्थापित करने का मामला पुरजोर ढंग से उठा रही है। उन्होंने कहा कि परवाणु में 180 बीघा भूमि में एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और 200 बीघा अतिरिक्त भूमि शीघ्र ही चिन्हित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है जोकि राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की गति को पुनः प्राप्त करने के विषय पर आयोजित इस वार्षिक अधिवेशन के परिणाम इसकी भावना को बनाये रखने में दीर्घकालिक सिद्ध होंगे।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने राज्य सरकार और उद्योग जगत के मध्य एक सेतु के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ आभार जताते हुए कहा कि इससे राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और उद्योगपतियों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश में कोविड महामारी के बावजूद 41000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग करने में राज्य सरकार सफल रही है। उन्होंने राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उद्यमियों का आभार भी व्यक्त किया।

भारतीय उद्योग परिसंघ के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष अभिमन्यु मुंजाल ने भी इस अवसर पर अपना संबोधन दिया।

भारतीय उद्योग संघ के निवर्तमान अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया कि बृहद् परवाणु औद्योगिक विकास प्राधिकरण और काला अम्ब – पावंटा साहिब विकास प्राधिकरण की स्थापना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक आधारभूत संरचना प्रदान करते हुए इन्हें रहने योग्य बनाने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इन दो औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का निर्णय मील पत्थर साबित होगा और यह राज्य में विश्वस्तरीय स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक नगर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

सीआईआई हि.प्र. राज्य परिषद को मिले नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता तथा गगन कपूर को क्रमशः सीआईआई हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद वर्ष 2022 – 23 का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

सुबोध गुप्ता माइक्रोटेक ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबन्धन निदेशक है, जिनका पावर सोल्यूशन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुभव है तथा गगन कपूर पुलकित इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो पैकेजिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं।

मुख्यमंत्री ने ढली में 49 करोड़ रुपये लागत की डबल लेन सुंरग की आधारशिला रखी

शिमला। प्रदेश सरकार शिमला के प्राचीन वैभव को बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है और इसके लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत शहर में विभिन्न कार्य किए

जा रहे हैं, ताकि लोगों को इनका समुचित लाभ मिल सके।

यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ढली में लगभग 49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली डबल लेन सुंरग की आधारशिला रखने के उपरान्त कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ढली की पुरानी सुंरग वर्षों पूर्व 1852 ई. में निर्मित की गई थी और अब 147 मीटर लम्बी इस नई डबल लेन सुंरग से यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर का निरंतर विकास होने से इसका व्यापक विस्तार हुआ है और ऐसे में प्रभावी यातायात प्रबन्धन के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक हो जाता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत सभी कार्य तीव्र गति से पूर्ण हों। उन्होंने कहा कि हालांकि यह परियोजना वर्ष 2016 में प्रारम्भ की गई थी, परन्तु इसने वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में ही गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के लिए 70 करोड़ रुपये की लागत की पेयजल आपूर्ति योजना रिकॉर्ड समयावधि में पूर्ण करके शहर में पेयजल संकट की समस्या का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के लिए 1813 करोड़ रुपये की एक नई पेयजल आपूर्ति परियोजना भी तैयार की जा रही है जिसका कार्य पूर्ण होने पर शहर में आगामी 100 वर्षों तक पानी की समस्या का हल हो सकेगा।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नई सुंरग के निर्मित होने से इस मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही और सुगम हो सकेगी। यह सुंरग शिमला जिला के कसुम्पटी और शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सड़कों को चौड़ा करने, पैदल पुलों, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि से संबंधित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 16500 मामलों का निपटारा किया गया

शिमला/शैल। प्री – लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 12 मार्च, 2022 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ दो बार आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, एच.पी. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपमंडल विधिक सेवा समिति, पालमपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा /धर्मशाला में राष्ट्रीय लोक अदालत की लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।

कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 49455 मामले उठाये गये, जो वर्ष 2014 के बाद से सबसे अधिक हैं, जिनमें से लगभग 16500 मामलों का निपटारा/ निपटान किया गया जो कि वर्ष 2015 के बाद सबसे अधिक है और लगभग 53,72,52,724/- रु0 की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को शाम 5:00 बजे तक वसूल/पुरस्कार दिया गया।

अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार आने वाले समय में मोटर वाहन चालान के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की जायेंगी तथा मामलों के त्वरित निपटान के लिए ई-लोक अदालत आयोजित की जायेगी।

हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को देय राशि का चरणबद्ध तथा नियमित रूप से भुगतानःबिक्रम सिंह

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है तथा कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों की देय राशि का चरणबद्ध तथा नियमित रूप से भुगतान किया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों के सभी वर्गों के वेतन, भत्ते इत्यादि तय समय अवधि के दौरान दिये जा रहे हैं। राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम में वर्षों से चली आ रही घाटे की नीति को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। निगम में पैन्शन भोगियों को भी उनकी मांग तथा अधिकारों के अनुरूप समय-समय पर देय राशि का भुगतान किया जा रहा है। पैन्शन भोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में पैन्शनरों की देय राशि का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया है।

बिक्रम सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल में पैन्शनरों को डी.सी.आर.जी. के रूप में 105.50 करोड़ रुपये की धनराशि की अदायगी की थी, जबकि वर्तमान सरकार मात्र चार वर्षों में ही इस मद पर 116.42 करोड़ रुपये की अदायगी कर चुकी है।

इसी प्रकार पिछली सरकार ने पैन्शनरों को लीव एनकैशमैन्ट के रूप में 70.50 करोड़ रुपये की अदायगी की थी, जबकि वर्तमान सरकार मात्र चार वर्षों में 69.89 करोड़ रुपये की अदायगी कर चुकी है।

चिकित्सा बिलों के एवज़ में पिछली सरकार ने पैन्शनरों को 7.53 करोड़ रुपये की अदायगी की, जबकि वर्तमान सरकार इस पर 12.23 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर चुकी है।

पैन्शन व कम्युटेशन की मद पर पिछली सरकार ने पैन्शनरों को 408.87 करोड़ रुपये प्रदान किए, जबकि वर्तमान सरकार अब तक 620.04 करोड़ रुपये की अदायगी कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में पैन्शनरों को कुल 592.40 करोड़ रुपये की अदायगी की थी, जबकि वर्तमान सरकार मात्र चार वर्षों में ही 818.58 करोड़ रुपये की अदायगी कर चुकी है। इसके अलावा पिछली सरकार के कार्यकाल में पैन्शन के 278 मामले लम्बित थे, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मात्र तीन मामले लम्बित हैं। इसी प्रकार 31 दिसंबर, 2017 तक पैन्शन के लम्बित मामलों में 12.04 करोड़ रुपये की अदायगी लम्बित थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 31 जनवरी, 2022 तक मात्र 16 लाख रुपये की अदायगी लम्बित है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के 177 पैन्शनरों के पक्ष में माह मई, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक मात्र सात महीनों की अवधि में पैन्शन व कम्युटेशन के रूप में 10.03 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं।

हिमाचल में अब महिला सुरक्षा होगी और चाक चौबंद:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि महिला सुरक्षा केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा सर्वोपरि रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से केवल महिला वर्ग का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का हित और भविष्य जुड़ा हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हमीरपुर में आयोजित महिला सुरक्षा कवच कार्यक्रम में कहा

कि महिला सुरक्षा को चाक चौबंद करने और प्रदेश के एक एक कोने में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है।

ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हीरो मोटोकॉर्प के सहयोग से हिमाचल प्रदेश पुलिस को 108 मोटरसाइकिलें भेंट करके 'महिला सुरक्षा कवच' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये मोटरसाइकिलें प्रदेश के छह जिलों चंबा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, काँगड़ा, सिरमौर और मंडी के थानों एवं चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए उपयोगी होंगी तथा इनसे महिला अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।

महिला सुरक्षा कवच को घर घर पहुंचाने के मकसद से हमीरपुर के स्कूल मैदान में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मुख्य अतिथि और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से मापी जा सकती है और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार तो कृष्ण से पहले राधा और राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि नारी ही नर की शक्ति है और बिना नारी के सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि घर का काम हो, सामाजिक जीवन हो या वैश्विक मंच महिलाओं ने सदैव अपनी भूमिका का ज़िम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया है।

ठाकुर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर हमारे सामने है, यह दिन महिलाओं की प्रतिभा, उनकी क्षमता और उनकी निष्ठा को सम्मानित करने का महिलाओं के कार्यो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि पूरे भारत विशेषकर हमारे हिमाचल में हमारी मातृशक्ति खेतों खलिहानों में, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग जगत और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समाज निर्माण व कार्य प्रतिपादन की दिशा में सराहनीय भूमिका निभा रही हैं।

सभी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की महिलाओं ने हमेशा नेतृत्व क्षमता और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। हाल ही के दिनों में महिलाओं से जुड़े कई कानूनों में सुधार भी किया गया है जिससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कई गुना बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रदेश में महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आज भी प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें सुनने को मिलती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कदम उठाती रही है। 108 मोटरसाइकिल पुलिस को वितरित करने की यह पहल इस दिशा में और मजबूती लायेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में 108 संख्या का बहुत महत्व है और इसे अपने आपमें पूर्ण संख्या माना जाता है। इसी के मद्देनजर महिला सुरक्षा कवच में मोटरसाइकिलों की संख्या 108 रखी है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं में भरोसा बढ़ेगा और वे अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ आगे आ पायेंगी तथा अपनी उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर पायेंगी।

अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला सुरक्षा कवच के लिए हीरोमोटोकॉर्प का आभार जताया और कहा कि यह कंपनी की सामाजिक प्रतिबद्धता साबित करता है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू का भी आभार जताया। उन्होंने विश्वास जताया कि मोटरसाइकिलों का यह बेड़ा प्रदेश की महिलाओं को और सशक्त करेगा जिससे वह समाज में बराबरी हासिल करने में सफल हों।

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस अवसर पर कहा कि किसी भी महिला के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा साहस हो सकती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग को 108 मोटरसाइकिल प्रदान करने के इस कदम से हमारे राज्य की महिलाएं वास्तव में अधिक साहसी महसूस करेंगी और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को और बढ़ायेंगी।

धूमल ने कहा कि हमीरपुर लोकसभा के सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशेष रूप से प्रदेश के नागरिकों विशेषकर महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया है। रोजगार सृजन कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, छात्राओं के लिए अनुभवात्मक दौरों, अस्पताल – सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा से लेकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुनिश्चित किया है कि हमारी माताओं, बेटियों और बहनों को स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान को महसूस करने के लिए सर्वोत्तम अवसर मिले।

धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हमेशा मानवता की सेवा के लिए खड़ा रहा है और उनकी सेवा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है जो मानव अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से व्यावसायिकता, अखंडता को दर्शाता है। धूमल ने कहा कि 108 मोटरसाइकिलों के जुड़ने से यह महिला सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति उनके संकल्प को और मजबूत करेगा।

ओलम्पियन मीराबाई चानू ने कहा कि किसी भी महिला को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, एक सुरक्षित वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुराग ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग को महिला सुरक्षा और सुरक्षा विभाग को 108 मोटरसाइकिल प्रदान करने का यह कदम हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करेगा। मैं सभी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।

इस कार्यक्रम में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा कि महिलाएं यदि चाहें तो आसमान छू सकती हैं और एथलेटिक्स में महिलाओं ने यह बार बार साबित करके दिखाया है। मगर हमारी मेहनत और लगन के साथ साथ परिवार, समाज और सरकार का सहयोगी भी जरूरी है। जब हिमाचल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और महिलाओं में यह विश्वास जगेगा कि उन्हें सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है तो उनमें अपने लक्ष्य को पाने का आत्मविश्वास बढेगा। अनुराग ठाकुर जी की यह पहल इस दिशा में बहुत बडा कदम है। अब हिमाचल की बेटियां भी बेफिक्र होकर आसमान छूने को निकल पड़ेंगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है।

इस मौके पर पुलिस के बैंड ने अपने संगीत से सबका मन मोह लिया जबकि जांबाज महिला पुलिस के हैरतअंगेज बाइक कारनामों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया ।

कार्यक्रम के अंत में श्री अनुराग ठाकुर ने 108 मोटरसाइकिलों को हमीरपुर में हरी झंडी दिखाई।

महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए ठाकुर ने एक स्तन कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग कैंप का भी उद्घाटन किया। यह कैंप अस्पताल – सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा और मनोचिकित्सक पिंकी जाधव की ओर से लगाया गया है।

प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धः जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला मंडी के धर्मपुर स्थित चोलथरा में आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित महिला स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम की शिमला

से वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की।

इस अवसर पर महिला दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिवस महिलाओं के सम्मान और समृद्धि के प्रति अपने संकल्प को दोहराने का भी एक मौका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं में उद्यमिता की भावना का पोषण करने से उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो, इस ध्येय की ओर निरंतर आगे बढ़ने में प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 32000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें लगभग 2 लाख 50 हजार से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। वित्त वर्ष 2022 – 23 के बजट में महिलाओं की सहायता के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत ग्राम संगठन से जुड़े स्वयं सहायता समूह को रिवाल्विंग फंड में 25 हजार रुपये की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉप – अप के रूप में दी जाएगी। उन्होने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1700 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 9000 रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके प्रदेश सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 4550 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 6100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसको सम्मिलित करके प्रदेश सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में 3100 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है। आंगनबाड़ी सहायिका को प्रति माह 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसे सम्मिलित करके प्रदेश सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3700 रुपये की प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है।

मुख्यमंत्री ने आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा समाज कल्याण की दिशा में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्था ने कोरोना संकट काल के दौरान उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर के विकास में महिलाओं की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की बेटियां देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर प्रदेश और धर्मपुर का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और अधिकांश विकास परियोजना को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यो की जानकारी भी दी।

आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा बंदना गुलेरिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और संस्था की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वकांक्षी योजनाओं से महिलाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है।

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर मुख्यमंत्री के साथ शिमला में उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी, अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर, विशेष ओलंपिक की अध्यक्षा डॉ. मल्लिका नड्डा, मृदुला प्रधान, रशिम धर सूद, कंगना रनौत, वरिष्ठ अधिकारी कुमुद सिंह और प्रभा राजीव वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। चोलथरा में आयोजित कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. डेज़ी ठाकुर, वंदना गुलेरिया सहित वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

हिमाचल में आप के चुनाव लड़ने के ऐलान से उठते कुछ सवाल

शिमला/शैल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद पार्टी ने हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनाव लड़ना उसका अधिकार है इसलिए चुनाव लड़ने पर सवाल नहीं उठाये जा सकते। लेकिन चुनावों से देश/प्रदेश और उसकी जनता का भविष्य तय होता है इसलिए चुनाव लड़ने वाला चाहे कोई राजनीतिक दल हो या व्यक्ति उसकी नीयत नीति और राजनीति को समझना आवश्यक हो जाता है। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह सवाल इसलिये अहम हो जाते हैं कि उसने पंजाब जीतने के बाद यह दावा किया है कि भाजपा का विकल्प होने का दम कांग्रेस में नहीं वरन आप में है। आप को अभी किसी पूर्ण राज्य में सरकार बनाने और चलाने का पहली बार पंजाब में मौका मिला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल से देश और राज्यों को चलाने का दावा कर रही है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर वहां की सरकार के अधिकार बहुत सीमित हैं। केजरीवाल सरकार का उप राज्यपाल से टकराव चला ही रहता है। केजरीवाल सरकार प्राय: यह आरोप लगाती रहती है कि केंद्र सरकार उसे चलने नहीं देती है। अधिकारों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंची है। केजरीवाल तीन बार प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन लोकसभा लगातार हार रहे हैं। दिल्ली की नगर निगम पर भी उसका कब्जा नहीं है। ऐसा क्यों है यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसका कर राजस्व पूरे देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को वेतन केंद्र सरकार देती है ऐसा अन्य राज्यों में नहीं है।

अभी आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड और गोवा में भी सरकार बनाने के पूरे दावों के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन वहां पर उसे कोई सफलता नहीं मिली है। बल्कि उसका चुनाव लड़ना भाजपा की जीत का एक बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आप इसी भूमिका में रहा है। लेकिन पंजाब में उसे प्रचंड बहुमत मिला है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि एक ही वक्त में इतना बड़ा विरोधाभास कैसे घट गया? क्या पंजाब की जनता कांग्रेस से मुक्ति चाहती थी क्योंकि पंजाब में जनसंघ से लेकर भाजपा तक की अकाली दल के सहारे ही सत्ता में भागीदारी रही है। इस बार जब कृषि कानूनों के कारण अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया तो स्वभाविक रूप से वहां पर भाजपा का कुछ भी दांव पर नहीं रहा। भाजपा को जो चुनौती राष्ट्रीय दल कांग्रेस से है वह किसी भी क्षेत्रीय दल से नहीं है। आज भी भाजपा और कांग्रेस में लोकसभा की 200 सीटों पर सीधी टक्कर है। इसलिए भाजपा का यह प्रयास रहेगा कि वह कांग्रेस को कमजोर करने के लिये किसी दल का परोक्ष/अपरोक्ष में साथ ले। इस समय देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर राष्ट्रीय हितों को दलों के हित से पहले रखना होगा।

2014 में अन्ना आंदोलन जिन मुद्दों पर आया था उन में भ्रष्टाचार और महंगाई तथा बेरोजगारी सबसे प्रमुख थे। इन मुद्दों पर कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय करार दे दिया गया था। काले धन के बड़े-बड़े आंकड़े परोस कर हर आदमी के खाते में पन्द्रह-पन्द्रह लाख आने का सपना दिखाया गया था। क्या 2014 के वादे पूरे हुये हैं। हर चुनाव में पुराने मुद्दों को भुलाकर नये मुद्दे गढ़े जाते रहे हैं। लेकिन यह सवाल नहीं पूछा गया कि यह दावे और वादे पूरे क्यों नहीं हुये। जिस चीन का डर देश को लगातार परोसा जा रहा है उसी के साथ व्यापार भी क्यों बढ़ता जा रहा है। 2014 से लगातार देश भाजपा और मोदी पर विश्वास करता आ रहा है। लेकिन इस विश्वास का प्रतिफल जनता को महंगाई और बेरोजगारी के रूप में क्यों दिया जा रहा है। विनिवेश और मौद्रीकरण के नाम पर राष्ट्रीय संपत्तियों को प्राइवेट सैक्टर के हवाले क्यों किया जा रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता क्यों खत्म हो रही है। इसे बहाल करने के लिए पुन: बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में ही विपक्ष सरकार से कर्जो और केंद्रीय सहायता पर श्वेत पत्र की मांग कर रहा है। क्या आप इन सवालों को चुनावी मुद्दा बनायेगा या सिर्फ कुछ चीजें मुफ्त देने के वायदों से ही जनता को ठग लेगा।

आप से यह सवाल इसलिए किये जा रहे हैं क्योंकि केजरीवाल अन्ना आंदोलन का प्रतिफल है। अन्ना आज सारे परिदृश्य से गायब है। लेकिन केजरीवाल भी इन मुद्दों पर खामोश हैं। इसलिए आज जब केजरीवाल की आप प्रदेश में सरकार बनाने के दावे के साथ चुनाव लड़ने जा रही है तो उसके हर आदमी से यह सवाल पूछने आवश्यक हो जाते हैं। अन्ना का आंदोलन संघ से प्रायोजित था यह सामने आ चुका है। उस आंदोलन का अन्ना के बाद दूसरा बड़ा नाम केजरीवाल है। केंद्र की मोदी सरकार इसी आंदोलन का परिणाम है। इसलिए मोदी सरकार पर उठने वाले हर सवाल सवाल का जवाब केजरीवाल और उसकी टीम से मांगना आवश्यक हो जाता है।

- केजरीवाल और मोदी सरकार दोनों अन्ना आंदोलन के परिणाम है
- इस नाते केंद्र पर उठते सवालों का जवाब केजरीवाल से मांगना जरूरी हो जाता है

श्वेत पत्र की मांग

.....पृष्ठ 1 का शेष

कार्यो के लिये पूंजीगत व्यय होता है और यह खर्च पूंजीगत प्राप्तियों से किया जाता है। यह पूंजीगत प्राप्तियां भी सक्ल ऋण होती हैं और शायद इस ऋण को कुल कर्ज में नहीं दिखाया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां वह ऋण होता है जो धन सरकार के पास कर्मचारियों और जनता का किसी न किसी रूप में जमा रहता है। जिसे अपनी सुविधा अनुसार सरकार अदा करती है। यदि कर्ज के इन आंकड़ों को भी जोड़ा जाये तो शायद कर्ज की स्थिति और भी गंभीर हो जाये।

सरकार जो बजट पेश करती है उसमें पूरे वर्ष में खर्च किये जाने वाले धन का आंकड़ा रहता है। इस बार वर्ष 2022-23 में सरकार कुल 51365 करोड खर्च करेगी। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 50192 करोड का था। इस तरह केवल करीब 2 प्रतिशत की वृद्धि इस बार की गयी है। जबकि इस दौरान महंगाई दस प्रतिश्त से भी अधिक बढ़ी है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस बार केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के बजट में 10%, मनरेगा में 25.5%, पीडीएस में 28.5%, रासायनिक खाद में 24% फसल बीमा में 3%, पेट्रोल में 10% और जल जीवन मिशन में 1.3% अपने बजट में कटौती की है। केंद्रीय बजट में हुई इन कटौतीयों का राज्यों के आवंटन पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप इन मदों में प्रदेश को इतना कम पैसा मिलेगा ऐसे में प्रदेश सरकार को 51365 करोड का खर्च पूरा करने के लिये और भी ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा क्योंकि चुनावों में जाना है। इसलिये इस वस्तुस्थिति में प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है की यह इतना कर्ज और केंद्र से मिली सहायता कहां खर्च की गयी है।

क्या प्रदेश के बढ़ते कर्ज

...पृष्ठ 1 का शेष

कि जब प्रदेश में स्थापित उद्योगों ने सिर्फ सरकार पर कर्ज बढ़ाने का ही काम किया है तो फिर इन्हें आर्थिक सहायता क्यों दी जानी चाहिए। इस परिदृश्य में सरकार को अपनी उद्योग नीति पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता हो जाती है। आज सवाल प्रदेश के विकास और यहां के लोगों को रोजगार मिलने का है। इसके लिये हिमाचल निर्माता स्व. डॉ. परमार की त्रिमुखी वन खेती से बेहतर और कोई नहीं रह जाती। यदि प्रदेश को बढ़ते कर्ज के चक्रव्यू से बाहर निकालना है तो उद्योग नीति पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अभी तक कोई भी सरकार इस बढ़ते कर्ज के कारणों का खुलासा नहीं कर पायी है। आज तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खुलेआम औद्योगिक निवेश के लिए आयोजित निवेश आयोजनों में भाग ले रहे हैं। जबकि इससे उनकी निष्पक्षता पर स्वभाविक रूप से सवाल उठ रहे हैं और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है।